भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

प्रेस विज्ञप्ति 3 जून 2011

बस्तर में सेना की तैनाती का विरोध करो!
'प्रशिक्षण' एक बहाना है! जनता को गुमराह करने का हथकण्डा है!!
'आत्मरक्षा' के नाम पर सेना को हमला करने का अधिकार देने का मतलब है आदिवासियों के कत्लेआम और अत्याचार की छूट!

कांकेर में सेना की पहली टुकड़ी के पहुंचने के साथ ही बस्तर में भारतीय सेना की औपचारिक तैनाती की प्रक्रिया शुरू हो गई। लेकिन इस बात को छुपाते हुए यह झूठा प्रचार किया जा रहा है कि सेना यहां प्रशिक्षण के लिए आ रही है न कि माओवादियों से लड़ने। यह भी बताया जा रहा है कि माओवादियों के हमलों से 'आत्मरक्षा' के नाम पर रक्षा और विधि मंत्रालयों ने 'मार्गदर्शी सिद्धांत' तय किए हैं जिसका खुलासा करने को फिलहाल कोई तैयार नहीं है। गौरतलब है कि वायुसेना को 'आत्मरक्षा' के लिए हमले करने का अधिकार पहले ही दिया जा चुका है।

देश की जनता को गुमराह करने के लिए तथा जनवादी ताकतों की ओर से उठ रहे विरोध को ध्यान में रखते हुए ही केन्द्र व राज्य सरकारें सोची-समझी साजिश के तहत 'प्रशिक्षण' का बहाना कर रही हैं। सच्चाई यह है कि देश की जनता के खिलाफ पहले से जारी युद्ध में अब सेना को मोर्चे पर लगाया गया है। और 'प्रशिक्षण' भी यही युद्ध लड़ने के लिए। कश्मीर और पूर्वोत्तर के इलाकों के बाद अब देश के बीचोबीच, अत्यंत दबी-कुचली जनता के खिलाफ सेना का प्रयोग किए जाने वाला है। कश्मीर और पूर्वोत्तर इलाकों की तरह बस्तर में भी काला कनून एएफएसपीए (सशस्त्र बलों का विशेषाधिकार कानून) को लागू किए जाने की आशंका सच में बदलती नजर आ रही है।

'आत्मरक्षा' के अधिकार के नाम से थलसेना और वायुसेना को सरकारों ने दरअसल जनता पर हमले करने का अधिकार दे दिया है। क्योंकि यहां यह फर्क करने का कोई पैमाना निर्धारित नहीं है कि यहां कौन माओवादी लड़ाकू है और कौन आम नागरिक है। 2005 से लेकर पहले सलवा जुडूम और अभी ऑपरेशन ग्रीन हंट के नाम से लगातार चलाए जा रहे दमन अभियानों के तहत सरकारी सशस्त्र बलों द्वारा 700 से ज्यादा गांवों को जला दिया गया; 1500 से ज्यादा आदिवासियों की हत्या की गई; सैकड़ों महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया; फसलें जलाई गईं; घर लूटे गए; और दसियों हजार आदिवासियों को अपना घरबार छोड़कर पलायन करने पर मजबूर किया गया। हाल ही में चिंतलनार क्षेत्र में सरकारी सशस्त्र बलों द्वारा मचाई गई बर्बरता एक ताजा भर उदाहरण है। अब सेना की तैनाती और उसे 'आत्मरक्षा' के नाम से दिए जा रहे अधिकारों से आदिवासियों के नरसंहारों और बर्बरतापूर्ण कार्रवाइयों में भारी इजाफा होगा। इससे समूचे आदिवासी कौम के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लग जाएगा। खासकर माड़ अंचल के मूलनिवासी माड़िया जन जाति के जल-जंगल-जमीन के साथ-साथ उनका प्राचीनतम सांस्कृतिक धरोहर भी मिट जाएगा।

आज जबरिया जमीन अधिग्रहण के खिलाफ देश भर में तीखी बहस छिड़ी हुई है। खासकर उत्तरप्रदेश के संदर्भ में कांग्रेस, भाजपा समेत सभी शोषक वर्गीय राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए किसानों की जमीन के अधिग्रहण के विरोध में बयानबाजी कर खुद को 'किसानों के चैम्पियन' घोषित कर रही हैं। लेकिन सेना के प्रशिक्षण के नाम से एक अत्यंत पिछड़े आदिवासी इलाके में हो रहे भारी जमीन अधिग्रहण को लेकर ये सारे 'चैम्पियन' चुप हैं। भाजपाई रमन सरकार ने प्रस्तावित तीन प्रशिक्षण स्कूलों में से एक के लिए नारायणपुर जिले के माड़ क्षेत्र में सेना को चुपचाप 750 वर्ग किलोमीटर जमीन सौम्पने का फैसला ले लिया। 'पांच रुपए में किलो चना' जैसी सस्ती योजना से वाहवाही लूट रहे रमनसिंह का असली चेहरा अब छुपाए नहीं छुप रही है। न इस पर कोई चर्चा हुई और न

ही कोई सलाह-मशविरा! 'पेसा' कानून और 5वीं अनुसूची का मजाक उड़ाया जा रहा है यहां। और स्थानीय माड़िया आदिवासियों को आज तक यह बात मालूम नहीं है कि जिस जमीन पर वे हजारों सालों से जी रहे हैं और जिस जंगल के सहारे वे अभी तक जिंदा हैं, वह अब उनका नहीं रहा। गौरतलब है माड़ का पूरा क्षेत्रफल 4,000 वर्ग किलोमीटर है जिसका करीब पांचवां हिस्सा फिलहाल सेना के हवाले किया जाने वाला है। आगे इसमें विस्तार होने की बात भी चल रही है। इधर सेना की गाड़ियां बस्तर के लिए रवाना हुईं और उधर स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया (सेल) ने रावघाट परियोजना की निजीकरण की घोषणा करते हुए ग्लोबल टेंडर बुलाए जाने की बात की। इससे तस्वीर और भी साफ हो जाती है। यानी एक तरफ सेना का विशाल अड्डा रहेगा, तो दूसरी तरफ से रावघाट के पहाड़ों से बेशकीमती लोहा निकालने तथा कई अन्य जगहों में खदानें शुरू करने व आदिवासियों की जमीनें छीनने के लिए दौड़ते हुए आएंगी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां! अब इस बात को समझना मुश्किल नहीं है कि यहां कौन क्यों आ रहा है और उनके बीच क्या सम्बन्ध है!!

आज देश में लागू साम्राज्यवाद-निर्देशित नव-उदार नीतियों को माओवादी संघर्ष से राजनीतिक रूप से कड़ी टक्कर मिल रही है। खासकर आदिवासी बहुल वन इलाकों में मौजूद अपार खनिज सम्पदाओं का दोहन करने पर आमादा बहुराष्ट्रीय व बड़े पूंजीपतियों की कम्पनियों की लूटखसोट के खिलाफ जारी आदिवासियों के संघर्ष और उनके संघर्षों की अगुवाई कर रहे माओवादी देश के शासक वर्गों और उनके साम्राज्यवादी आकाओं के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए। छत्तीसगढ़, झारखण्ड, ओड़िशा, आंध्रप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में राज्य सरकारों और कॉर्पोरेट कम्पनियों के बीच किए गए सैकड़ों एमओयू (संधि-पत्र)) लम्बित हैं जिन पर जनता के विरोध के चलते अमल नहीं हो पा रहा है। खासकर दण्डकारण्य में खदानों, बड़े बांधों और भारी उद्योग आदि कॉर्पोरेट कम्पनियों की कई परियोजनाएं जनता के संगठित विरोध व प्रतिरोध के चलते शुरू ही नहीं पा रही हैं। यानी एक शब्द में कहें तो दण्डकारण्य में शोषक-लुटेरों के 'विकास' का भारी बुलडोजर आगे बढ़ नहीं पा रहा है। यही वजह है कि उन्होंने जनता के खिलाफ यह युद्ध छेड़ रखा है और इसमें अब सेना को उतार दिया है।

बस्तरिया आदिवासियों ने शोषण, अन्याय, दमन और पराये शासन के सामने कभी अपना सिर नहीं झुकाया। अंग्रेजी उपनिवेशवादियों के खिलाफ कई विद्रोह करने का उनका गौरवशाली इतिहास रहा है। 1910 के महान भूमकाल के समय अग्रेजों ने बस्तरिया जनता के खिलाफ सेना का प्रयोग किया था। आज सौ साल बाद फिर एक बार सेना उतार दी गई है ताकि उनके न्यायपूर्ण संघर्षों को खून की नदियों में डुबोया जा सके। हम समूचे दण्डकारण्य की जनता का आह्वान करते हैं कि इस चुनौती का बहादुरी के साथ स्वीकार करें। जनता ही इतिहास का निर्माता है। अत: अंतिम विजय जनता की ही होगी।

हमारी दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी देश के तमाम जनवादपसंदों, मानवाधिकार संगठनों, विस्थापन-विरोधी संगठनों, आदिवासी संगठनों और आदिवासियों के तमाम शुभचिंतक बुद्धिजीवियों, लेखक-कलाकारों और मीडियाकर्मियों से यह अपील करती है कि वे बस्तर क्षेत्र में सेना की प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना और उसके लिए किए जा रहे जमीन अधिग्रहण के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। प्रशिक्षण स्कूल खोलने के बहाने जनता के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए हो रही सेना की तैनाती का विरोध करते हुए 'भारतीय सेना, बस्तर से वापस जाओ' के नारे के साथ जन आंदोलन निर्मित करें। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कॉर्पोरेट कम्पनियों के साथ किए गए तमाम एमओयू को रद्द करने तथा जबरिया जमीन अधिग्रहण की तमाम योजनाओं को भंग करने की मांग करें।

Gudsa Usendi

(गुड्सा उसेण्डी)

प्रवक्ता

दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)